

## संयुक्त राज्य अमेरिका का ऋण सीमा संकट

### प्रलम्बित के लिये:

संयुक्त राज्य अमेरिका का ऋण सीमा संकट, संवधान का 14वाँ संशोधन, क्रेडिट रेटिंग, [वदिशी मुद्रा](#)

### मेन्स के लिये:

राजकोषीय घाटा और भारत सरकार द्वारा इसका प्रबंधन

## चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी सेक्रेटरी ने आगाह किया है कि यदि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस कर्ज़ की सीमा को बढ़ाने या नलिंबति करने हेतु किसी परणाम पर पहुँचने में वफिल रहता है तो **1 जून तक कर्ज़ का संकट उत्पन्न हो जाएगा**।

## अमेरिकी ऋण सीमा:

### परचिय:

- ऋण सीमा वह अधिकतम राशा है जो अमेरिकी सरकार को कानूनी रूप से अपने खर्चों एवं दायतियों को पूरा करने हेतु उधार लेने की अनुमति है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1917 में [प्रथम विश्व युद्ध](#) के दौरान हुई थी।
- ऋण सीमा का उद्देश्य प्रत्येक व्यय हेतु कॉन्ग्रेस से लगातार अनुमोदन की आवश्यकता के बनिा सरकार को खर्च में लचीलापन प्रदान करना है।
- अमेरिकी संवधान के तहत कॉन्ग्रेस के पास सरकारी खर्च को नयित्तरि करने का अधिकार है।
- अभी तक वर्तमान ऋण सीमा 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर नरिधारति की गई है। इसका मतलब यह है कि कॉन्ग्रेस की मंजूरी के बनिा सरकार इस राशा से अधिक उधार नहीं ले सकती है।

### वर्तमान गतरिध:

- वर्तमान गतरिध में रिपब्लिकन (वपिक्षी दल के सदस्य) शामिल हैं, जनिके पास प्रतनिधि सभा और डेमोक्रेट द्वारा संचालति सरकार में बहुमत है।
- रिपब्लिकन अमेरिकी ऋण सीमा को तब तक बढ़ाने से इनकार (यह तर्क देते हुए कदिश का ऋण अस्थरि है) कर रहे हैं जब तक कि सरकार खर्च में महत्तवपूर्ण कटौती और अन्य प्राथमकिकाओं को शामिल करने हेतु सहमत नहीं होती है।
  - वे यह सुनश्चिति करने के लिये कसिरकारी व्यय सीमति है, नकद सहायता, भोजन, टकिट और मेडकिंड जैसे कार्यकरमों से शर्तें जोडना चाहते हैं।
- दूसरी ओर राष्ट्रपति ऋण सीमा को बनिा किसी शर्त के स्वीकृत करने पर बल देते हैं, यह कहते हुए कि ऋण पर डफिॉल्ट करना गैर-परकराम्य है।
- इसने एक गतरिध को जन्म दिया और साथ ही यदसिमय-सीमा से पहले कोई समझौता नहीं किया जाता है तो डफिॉल्ट का संभावति जोखमि है।

## सरकार के डफिॉल्ट होने का प्रभाव:

### सरकारी डफिॉल्ट :

- अमेरिकी सरकार अपने वत्तिलीय दायतियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है जिसके परणामस्वरूप उसके ऋण भुगतान में डफिॉल्ट हो सकता है। यह अभूतपूर्व रूप से देश की अर्थव्यवस्था पर वनिाशकारी प्रभाव प्रदर्शति कर सकता है।

### आर्थिक मंदी:

- डफिॉल्ट होने से अमेरिकी वत्तिलीय प्रणाली के प्रतविश्रिवास में कमी आणी, जिससे वत्तिलीय बाज़ार अत्यधिक अस्थरि हो जाएंगे। यह व्यवसायों, नविशों और रोजगार को प्रभावति करते हुए गंभीर आर्थिक मंदी की स्थतिकाे प्रदर्शति कर सकता है।

- विश्लेषकों के अनुसार, डॉलर कमजोर होगा, शेयर बाजार गरिगे और लाखों लोग रोजगारवहीन हो सकते हैं।
- **डाउनग्रेड क्रेडिट रेटिंग:**
  - डफॉल्ट के परणामस्वरूप अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है, जिससे सरकार के लिये भवषिय में धन उधार लेना अधिक महंगा हो जाएगा। इससे देश के वित्त पर अधिक दबाव पड़ेगा तथा उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी।
- **वैश्विक प्रभाव:**
  - अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ गहरा संबंध है। डफॉल्ट का वशिव में व्यापक प्रभाव हो सकता है जिससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में व्यवधान प्रदर्शति हो सकता है और साथ ही यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है।

## ऋण सीमा डफॉल्ट से बचने के उपाय:

- **14वाँ संवधान संशोधन:**
  - संवधान का **14वाँ संशोधन** राष्ट्रपति को वधियकि के समर्थन के बनिा स्वयं की ऋण सीमा को बढ़ाने का अधिकार देता है।
    - संवधान के 14वें संशोधन में कहा गया है कि **सार्वजनिक ऋण की वैधता पर "प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।"** यह इस तथ्य को भी शामिल करता है कि **ऋण में चूक असंवधानिक है** और इसे रोकने के लिये कार्रवाई की जा सकती।
- **आपातकालीन उपाय:**
  - कोषागार वभिग के पास कुछ आपातकालीन उपाय होते हैं **जनिका प्रयोग वह ऋण सीमा तक पहुँचने के बाद भी सरकार के बलिों का भुगतान जारी रखने के लिये** कर सकता है।
  - यह उपाय अस्थायी राहत तो प्रदान कर सकते हैं, कति यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
  - ये स्थायी समाधान होने तक यह सरकार को सुचारु रूप से कार्य करने के लिये कुछ समय प्रदान करते हैं।
- **द्वदिलीय समझौता:**
  - हालाँकि यदि अंतमि कषण तक सरकार और वपिकष के मध्य संवाद जारी रहता है तो **संभवतः ऋण सीमा बढ़ाने के लिये द्वदिलीय समझौता हो सकता है।** इसमें खर्च में कटौती या अन्य वित्तीय उपायों पर समझौता करना तथा इसके लिये आम सहमत वियक्त करना शामिल है।

## पूर्व के उदाहरण:

- ऐसी ही स्थिति विर्ष 2011 में नरिमिती हुई थी जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और प्रतनिधि सदन (House of Representatives) को वपिकषी दल के सदस्यों द्वारा नरित्तरति कयिा जाता था।
- एक समझौते पर पहुँचकर समय-सीमा से कुछ समय पहले संकट का समाधान कयिा गया था। इसके अंतरगत राष्ट्रपति ने संकट समाधान और ऋण सीमा को बढ़ाने के लिये कुल **900 बलियिन अमेरिकी डॉलर से अधिक के खर्च में कटौती** को लागू करने पर सहमत वियक्त की थी।

## भारत द्वारा प्रबंधति उधार एवं ऋण दायतिव:

- FRBM अधनियिम के अनुसार, भारत के पास एक औपचारिक ऋण सीमा तंत्र है, लेकिन अमेरिका की तरह पूरण राशिके मामले में ऋण सीमा नहीं है। इसलिये अमेरिका में ऋण सीमा की तुलना भारत में **राजकोषीय घाटे** के लक्ष्य से की जा सकती है।
  - भारत में यह लक्ष्य **सकल घरेलू उत्पाद** (Gross Domestic Product- GDP) के प्रतशित की सीमा में है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक पूरण राशिके।
- भारत सरकार वभिनिन तंत्रों और संस्थानों के माध्यम से उधार एवं ऋण दायतिवों का प्रबंधन करती है, जैसे कि:
  - **प्रतभूतयिों और बॉण्ड के माध्यम से धन एकत्र करना:** यह घरेलू बाजार में सरकारी प्रतभूतयिों, जैसे ट्रेज़री बलि और सरकारी बॉण्ड जारी करता है।
  - **राजकोषीय उत्तरदायतिव और बजट प्रबंधन (FRBM) अधनियिम:** यह भारत में **राजकोषीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन** के लिये एक वधियी ढाँचा प्रदान करता है। यह राजकोषीय घाटे तथा ऋण-से-GDP अनुपात के लिये लक्ष्य नरिधारति करता है, जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक राजकोषीय स्थरिता सुनश्चिति करना है। सरकार के उधार लेने के नरिणय FRBM अधनियिम में उल्लखिति सदिधांतों द्वारा नरिदेशति होते हैं।
  - **भारतीय रज़िरव बैंक (RBI):** RBI देश के उधार और ऋण के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिाता है। यह **केंद्र सरकार के बैंकर** के रूप में कार्य करता है और सरकारी प्रतभूतयिों को **जारी करने, नीलामी तथा व्यापार की सुवधि प्रदान करता है।** RBI सरकार के नकदी प्रवाह का प्रबंधन भी करता है तथा **ऋण लेन-देन के सुचारु नपिटान को सुनश्चिति करता है।**

## अमेरिकी ऋण सीमा का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- ऋण सीमा को बढ़ाने में वफिलता तथा बाद में अमेरिकी सरकार के चूक के जोखमि से **वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थरिता** बढ़ सकती है।
- एक ऋण सीमा संकट अमेरिकी डॉलर की साख तथा इसमें विश्वास को कम कर सकता है, जिससे इसमें मूल्यहरास हो सकता है। इस मूल्यहरास का **अन्य मुद्राओं और व्यापार संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।**
- एक ऋण सीमा संकट वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थरिता और विश्वासनीयता को कम कर सकता है। बाजारों में अनश्चितिता और भय के परणामस्वरूप **व्यापार और उपभोक्ता खर्च में कमी** आ सकती है तथा इसके साथ अमेरिका में ही नहीं बल्कि विश्व भर में **आर्थिक वकिस में बाधा** उत्पन्न हो सकती है।

## भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- **रुपए का अवमूल्यन:**
  - भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले मूल्यहरास हो सकता है, जिससे **आयात अधिक महँगा हो सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित रूप से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है।**
- **व्यापार व्यवधान:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है और **ऋण सीमा संकट से उत्पन्न कोई भी आर्थिक मंदी** भारतीय निर्यात की मांग को कम कर सकती है।
  - अमेरिका को कम निर्यात अमेरिकी उपभोक्ताओं पर निर्भर भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे **सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स** इत्यादि।
- **वदेशी मुद्रा पर प्रभाव:**
  - भारत के पास संयुक्त राज्य कोषागार समेत बड़ी मात्रा में **वदेशी मुद्रा भंडार** है। अमेरिकी ऋण के डिफॉल्ट या डाउनग्रेड के परिणामस्वरूप **इन नविशों पर नुकसान हो सकता है**, जो संभावित रूप से भारत के वदेशी मुद्रा भंडार तथा समग्र वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

## [स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/us-debt-ceiling-crisis>

